



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-14
08/01/2016

नये भवन भूकंपरोधी बने तथा सभी पुराने भवनों में रेक्टोफिटिंग हो— मुख्यमंत्री

पटना, 08 जनवरी 2016 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज होटल पाटलीपुत्रा अशोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण सूत्रीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुये कहा कि बिहार में नये भवन भूकंपरोधी बने तथा सभी पुराने भवनों में रेक्टोफिटिंग हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डिजास्टर रिस्क रिडक्सन रोड मैप 2015-2030 पर आयोजित वर्कशॉप के आयोजन में भाग लेकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मई 2015 में ही डिजास्टर रिस्क रिडक्सन पर इसी स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बाद 10 सूत्री घोषणा की गई थी। उसी के मद्देनजर एक रोड मैप तैयार की गई। उस रोड मैप पर आज आयोजित कार्यशाला में दो दिनों तक चर्चा होगी। डिजास्टर रिस्क रिडक्सन के लिए कुछ लक्ष्य रखे गये हैं। जान-माल की क्षति कम हो। प्रभावित लोगों की संख्या कम हो एवं आपदा पीड़ितों की संख्या घटे। आपदाओं को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते लेकिन आपदाओं से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोड मैप का मतलब एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत हमें निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन्डई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन मार्च 2015 के बाद बिहार पहला राज्य है जिसने राज्यस्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। आपदायें आती रहती हैं। बिहार ऐसा राज्य है, जो बाढ़, सुखाड़, भूकंप एवं चक्रवाती तूफानों जैसी आपदाओं को झेलता है। बिहार के बहुत सारे क्षेत्र सिसमिक जोन-4 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रैल 2015 में जो भूकंप आया था, उसका एपी0 सेन्टर हिमालय में था। लोगों का मानना है कि पृथ्वी के अन्दर जो उर्जा उलझा है, वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस संबंध में कई आर्टिकल आ रहे हैं। हम निरंतर यह देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ दिनों के अंतराल पर निरंतर भूकंप आ रहे हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बिहार में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। अप्रैल 2015 में यहाँ भूकंप के कई झटके लगे थे। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015-2030) जो 15 वर्षों के लिए बन रहे हैं, उस रोड मैप में यह बात स्पष्ट रूप से रहेगी कि नये मकान निश्चित रूप से भूकंपरोधी बने। पुराने सभी भवनों जिससे लोगों को तालूक है, जैसे— स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालयों एवं सरकारी भवनों का रेक्टोफिटिंग होनी चाहिये। सभी नये भवनों में भूकंपरोधी तकनीक अपनाया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2015 में आई भूकंप के बाद सरकार द्वारा यह घोषणा हुई थी कि जिनके मकान में किसी प्रकार के दरार दिखते हो तो तत्काल सूचित करें। लोगों ने इसकी सूचना दी। इंजीनियरों की टीम ने पर्यवेक्षण किया तथा इसके उपचार के लिए कार्य किये गये। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने आपदा के स्थिति में स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग पैटर्न (एसओपी0) बना दिया है। हर आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिये, तत्क्षण निर्णय लिया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से देखते रहे हैं कि जुलाई में बाढ़ आती है तो दिसम्बर में रिलिफ बंटता था। बाढ़ से हुई मृत्यु में मृतक के परिजन को दिसम्बर में सहायता दी जाती

थी लेकिन आज तत्क्षण प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जाती है तथा रिलिफ का बंटवारा होता है। मृत व्यक्ति को तो हम वापस नहीं ला सकते लेकिन उसके परिजनों के दुख में हम शामिल होते हैं। इससे तत्काल लोगों को सांत्वना मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार ऐसा विंटर आया है, जिसे लोग हॉट विंटर कह रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि शुरु में कुछ वर्षा हो जाती है, फिर वर्षा होती ही नहीं है, जब हम सुखाड़ घोषित कर डीजल सब्सिडी दे देते हैं तो बाद में वर्षा होती है। इस बार जाड़ा नहीं पड़ा तो गर्मी भी नहीं पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी तो वर्षा भी नहीं होगी। वर्षा नहीं हुई तो भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। बिहार अद्भूत राज्य है, जहाँ बाढ़ एवं सुखाड़ एक साथ आती है। लोगों को अचरज होती है कि किसी राज्य में एक साथ सुखाड़ और बाढ़ कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि भूकंप, बाढ़, तूफान एवं अन्य प्रकार की आपदायें कैसे आती हैं, इसी आधार पर रोड मैप तैयार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों के लिए यह चुनौती है कि आपदायें आयेगी तो हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन है। हमलोगों का दायित्व है कि आपदाओं का दुष्प्रभाव कम से कम कर सके। यही आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। हम काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण सूत्रीकरण कार्यशाला के बाद रोडमैप बनने पर ज्यादा कारगर होगा। ऐसा आधारभूत संरचना का निर्माण होगा जो सभी प्रकार के आपदाओं को झेल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे 7 निश्चय हैं। 7 निश्चय को क्रियान्वित किया जा रहा है। 7 निश्चय के अन्तर्गत हर घर में शौचालय बनाया जा रहा है। शौचालय ऐसा न बने कि भूकंप आने पर गिर जाये और लोगों को नुकसान हो जाये। शौचालय का निर्माण इस तरह से होगा कि वह आपदाओं को झेल सके। उन्होंने कहा कि 2008 में नेपाल के कुसहा में बांध टूटने पर बिहार को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बांध का निर्माण हो जो आपदाओं को झेल सके। रोड मैप होगा तो जोखिम का न्यूनीकरण होगा। उन्होंने कहा कि आपदा का दुष्प्रभाव कम हो, इस बात के लिए जो भी राशि खर्च होगी, वह उचित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड मैप बन जाने के बाद हम अपने राज्यों में यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका क्रियान्वयन हो। आधारभूत संरचना, कृषि रोडमैप, मानव विकास, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय हर क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की ऐसी भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। मुझे खुशी है कि आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने कार्यों को महत्वपूर्ण ढंग से निष्पादित कर रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण सूत्रीकरण कार्यशाला के नतीजे इतने अच्छे होंगे कि एक बेहतर रोड मैप बन पायेगा। आपदा प्रबंधन हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह इस तरह से लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है कि आपदा से बचाव हर आदमी के मन में एक संस्कार के रूप में विकसित होगा। सब लोगों के संयुक्त प्रयास एवं अभिरूचि से रोडमैप बनेगा।

मंत्री आपदा प्रबंधन श्री चन्द्रशेखर ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

बैठक में विशेष सचिव आपदा प्रबंधन श्री अनिरुद्ध कुमार ने स्वागत भाषण किया जबकि प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन ब्यास जी ने डिजास्टर रिस्क रिडक्सन रोडमैप (2015-2030) के संबंध में प्रकाश डाला।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे मंत्री श्री चन्द्रशेखर, उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री अनिल कुमार सिन्हा, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण श्री कमल किशोर, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन श्री उदय कांत मिश्रा, कंट्री रिपर्जनटेटिव यू0एन0 हैबिटेट इंडिया श्री एलेन ग्रिमार्ड, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री ब्यास जी, प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, डी0जी0 होमगार्ड श्री पी0एन0 राय, पूर्व सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण श्री के0एम0 सिंह, श्री मुजप्फर आलम, विशेष सचिव आपदा प्रबंधन श्री अनिरुद्ध कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
